RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 07 APRIL TO 13 APRIL 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 33 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

मई से सऊदी अरब से 35% कम कच्चे तेल की खरीद करेगा भारत

Page 3

लोकल लॉकडाउन भी अर्थव्यवस्था को पहुंचाएंगे गहरी चोट

Page 5

भारत की 5 टॉप माइलेज देनी वाली पेट्रोल कारें, टोयोटा और मारुती जैसी कंपनी भी हैं शामिल

Page 7

editoria!

छोटी बचत, बड़ा काम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार सुबह-सुबह यह ट्वीट करके सबको खुश कर दिया कि देश में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। खुशी की वजह यह थी कि एक दिन पहले ही सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम के इंटरेस्ट रेट में जबर्दस्त कटौती करने का ऐलान किया था। अगर ये इतना गंभीर मामला नहीं होता तो हल्के-फुल्के ढंग से यह सोचते हुए इसका मजा लिया जा सकता था कि सरकार ने अप्रैल फूल डे की पूर्वसंध्या पर लोगों के साथ ऐसा मजाक किया, जिसकी परिणति अगली सुबह एक सुखद अहसास में हुई। मगर करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े ऐसे फैसले हंसी-मजाक की चीज नहीं हो सकते। इसलिए जब वित्त मंत्री ने बढ़ोतरी का निर्णय वापस लेने की घोषणा करते हुए अपने ट्वीट में इसका कारण यह बताया कि ब्याज दरों में कटौती का फैसला गलती से ले लिया गया था, तो उस पर सहज ही विश्वास करना बहुतों के लिए मुश्किल हो गया। कई विपक्षी नेताओं ने तो आरोप लगाए कि फैसले की घोषणा करने के बाद सरकार को अहसास हुआ कि असम और पश्चिम बंगाल में हो रहे दूसरे दौर के मतदान में बीजेपी को इस फैसले का बड़ा नुकसान हो सकता है और इसीलिए सुबह-सुबह इसे वापस लेने की घोषणा कर दी गई। इस आरोप में सचाई हो या न हो, अगर सरकार की तरफ से वित्त वर्ष के आखिरी दिन अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में कटौती की घोषणा तय प्रक्रिया के मुताबिक की जाती है तो इसका साफ मतलब है कि सरकार में किसी न किसी स्तर पर इस पर सोच-विचार भी हुआ होगा। कोरोना महामारी के इस दौर में सरकारी राजस्व की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि सरकार अभी बहुत दबाव में है। लेकिन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में ऐसी कटौती सरकार को अपना खर्च कम करने में थोड़ी सहायता भले करे, आम लोगों की बचत को बुरी तरह प्रभावित करेगी। खास तौर पर रिटायर्ड बुजुर्गों को, जिनका गुजारा जीवन भर की बचत पर मिलने वाले ब्याज से चलता है। वे अपनी बचत की रकम ऐसी ही छोटी बचत योजनाओं में लगाते हैं क्योंकि यहां रिटर्न तो ठीकठाक मिलता ही है, पैसा भी सुरक्षित रहता है। यूं भी इनमें कमी का सिलसिला पिछले कई बरसों से चला आ रहा है। अब अगर और कटौती होगी तो लोगों को अधिक रिटर्न के लिए शेयर बाजार जैसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ऐतिहासिक तौर पर शेयरों ने निवेश के दूसरे सभी जरियों से अधिक रिटर्न दिया है, लेकिन बाजार के असामान्य उतार-चढ़ावों को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं। दूसरी बात यह कि बाजार के अप्रत्याशित रूप से बैठ जाने की स्थिति में इन्हीं छोटी बचत योजनाओं में लगा पैसा इकॉनमी का सहारा भी बनता है। इसलिए बेहतर होगा कि तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए छोटी बचत योजनाओं पर कुल्हाड़ी चलाने जैसे उपायों से बचा जाए।

GST e-invoice

क्या है जीएसटी में ई-इनवॉइस सिस्टम

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त वर्ष 2020-2021 के अंत तक ई-इनवॉइसिंग (e-invoicing) ने सफलतापूर्वक अपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं। वर्तमान में, 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले 75,000 से अधिक जीएसटीआईएन (25000 से अधिक इकाइयां/पैन से संबंधित) इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर इनवॉइस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के वाइस प्रेसिडेंट रवि किरन इदरा का कहना है कि हर महीने (जनवरी 2021 से) लगभग 7.3 करोड़ IRN (इनवॉइस रेफरेंस नंबर) जेनरेट हो रहे हैं। अब, 1 अप्रैल 2021 से, रु. 50 से 100 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबार भी ई-इनवॉइसिंग (e-invoicing) का लाभ ले सकेंगे। इस संदर्भ में, यह देखना महत्वपूर्ण है कि ई-इनवॉइसिंग बिजनेस इको-सिस्टम (e-invoicing Business Eco System) को पूरी तरह से कैसे बदलने जा रहा है।

कई फायदे हैं ई इनवॉयसिंग के

इस लिहाज़ से देखा जाए तो, ई-इनवॉइसिंग के कई फायदे हैं। कर अनुपालन या टैक्स कंपलायन्स व्यवसाय प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है, जीएसटी रिटर्न की प्री-पोपुलेशन, ई-वे बिल का ऑटो-जेनरेशन (जहां आवश्यक हो), फ्रॉड में कमी आदि ऐसे कई सकारात्मक नतीजे हैं हैं जो ई-इनवॉइसिंग के कारण संभव हो सके हैं। हाल ही में, सरकार ने भी संकेत दिया कि ई- इनवॉइसिंग जल्द ही ई-वे बिल सिस्टम की जगह लेगा और जीएसटी रिटर्न फाइल करने के मौजूदा तरीकों को बदल देगा। हालांकि, टैक्स कंपलायन्स की दृष्टिकोण से ये कुछ तात्कालिक लाभ हैं, लेकिन पूरे बिजनेस इको-सिस्टम को ई-इनवॉइसिंग के कई दूरगामी लाभ मिलेंगे।

डेटा एंट्री का एरर खत्म

ई-इनवॉइस का पेपरलेस होना डेटा एंट्री एरर को खत्म करने, रीकन्सिलीऐशन के मुद्दों को कम करने, लेन-देन वालों के बीच विवादों में कमी, पेमेंट साइकिल में तेजी, कागज की खपत में पर्याप्त कमी, प्रॉसेसिंग की लागत में कमी, बेहतर आंतरिक नियंत्रण और ऐसी तमाम सुविधाओं के कारण व्यवसायों की दक्षता को बढ़ाने में सहायक होगा। यही नहीं, ये नेटवर्क न केवल इनवॉइस के आदान-प्रदान का समर्थन कर सकते हैं, बल्कि अन्य डॉक्यूमेंट जैसे पर्चेज ऑर्डर और पेमेंट की प्रक्रिया में भी सहायक होंगे। इस प्रकार, ई-इनवॉइसिंग बिजनेस के एक दूसरे के बीच इनवॉइस भेजने और प्राप्त करने के तरीके में क्रांति लाने वाला है।

क्या है ई इनवॉयसिंग

'ई-इनवॉइसिंग' की विशेषताओं में मुख्य रूप से अधिसूचित पोर्टल पर इनवॉइस विवरण की रिपोर्टिंग और रेफरेंस नंबर जेनरेट करना शामिल है। इसके अलावा, यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि इनवॉइस के लिए एक समान मानक पर काम किया गया हो और इसे 'INV-01' के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक विशिष्ट कमर्शल इनवॉइस का मिश्रण है। यह मानक यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज (यूबीएल) पर आधारित है, जो भारतीय व्यवसाय की कार्यप्रणाली के लिहाज़ से काफी अनुकूल है। यह इनवॉइस के 'मशीन-रीडेबिलिटी' और व्यवसायों के बीच अत्यावश्यक 'इंटर-ऑपरेबिलिटी' के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यानी एक से दूसरे अकाउंटिंग/ ईआरपी सिस्टम में डिजिटल रूप से इनवॉइस के सीधे ब्रॉडकास्ट की अनुमति देकर। इसे प्राप्तकर्ता या रेसिपीएन्ट बिजनेस को जीएसटी सिस्टम से सीधे हस्ताक्षरित इनवॉइस JSON डाउनलोड करने के लिए सक्षम करके प्राप्त किया जा सकता है।

कारोबारियों को आसानी से मिलेगा कर्ज

कर्ज के दृष्टिकोण से भी देखें तो, बैंक और वित्तीय संस्थान (एफआई) कर्ज चाहने वाले व्यवसायों के फाइनेंशियल हेल्थ और कंपलायन्स प्रोफाइल की जांच करना पसंद करते हैं। शीघ्रता से कर-प्रस्तावों का निपटारा करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) की विशेषज्ञ समिति ने नोट किया कि बैंकों की प्रासंगिक सरोगेट डेटा तक पहुंच होनी चाहिए। बैंक, एनबीएफसी और अन्य फिनटेक प्लेयर्स विभिन्न स्रोतों से वित्तीय जानकारी के संग्रह और प्रसंस्करण को कारगर बनाने के लिए नवीन डिजिटल तकनीकों को अपना रहे हैं। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) की परिकल्पना करदाताओं के डेटा को साझा करने के लिए ऐसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स में से एक के रूप की गई है।

बैंकों के साथ रियल टाइम पर डेटा होगा शेयर

देश में बैंक और एफआई धीरे-धीरे पारंपरिक परिसंपत्ति-आधारित / रेटिंग-आधारित उधार से नकदी प्रवाह-आधारित उधार की ओर बढ़ रहे हैं। एमएसएमई के लिए यह बहुत फायदेमंद ट्रेंड है। ट्रेड रिसीवेबल को लिक्विड फंड में परिवर्तित करने के लिए श्एऐं की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक 'स्लो पेइंग' इनवॉइस हैं। एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के रूप में, ई-इनवॉइसिंग से बैंकों और एफआई के साथ रियल टाइम बेसिस इनवॉइस डेटा शेयर करना संभव होगा। सरकारी पोर्टल से डिजिटली हस्ताक्षरित इनवॉइस सप्लायर द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट के लिए एकल स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। पहले से फाइनेंस किए गए इनवॉइस को फ्लैग करना भी संभव होगा जिससे आपूर्तिकर्ता या सप्लायर द्वारा उसी इनवॉइस को किसी दूसरे फाइनेंसर को जमा करने की संभावना से बचा जा सकेगा। (शेष पृष्ठ 2 पर)

मई से सऊदी अरब से 35% कम कच्चे तेल की खरीद करेगा भारत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिफाइनरी कंपनियां अगले महीने सऊदी अरब से कम कच्चे तेल की खरीद करेंगी। कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच ईंधन की मांग घटी है। कच्चे तेल की खरीद में विविधीकरण के लिए भारतीय कंपनियां पश्चिम एशिया के बाहर से आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और तीन अन्य रिफाइनरी कंपनियों ने मई में सऊदी अरब से 1.5 करोड़ बैरल के मासिक औसत की तुलना में सिर्फ 65 प्रतिशत की खरीद करने का फैसला किया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने यह सूचना दी है।

भारत के आग्रह को नजरअंदाज किया था

भारत ने सऊदी अरब से कीमतों पर अंकुश रखने के लिये कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। सऊदी अरब ने भारत के इस आग्रह को नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने पिछले महीने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से पश्चिम एशिया से बाहर से आपूर्ति पर ध्यान देने को कहा। सूत्रों ने बताया कि आईओसी और अन्य रिफाइनरी कंपनियां सऊदी अरब या ओपेक देशों से निश्चित मात्रा के अनुबंध के स्थान पर हाजिर या मौजूदा बाजार से अधिक कच्चा तेल खरीदने का प्रयास कर रही हैं।

अमेरिका-नॉर्वे पर नजर

अपने इन प्रयासों के तहत कंपनियों ने गुयाना से लेकर नॉर्वे से नया कच्चा तेल खरीदा है। इसके अलावा खरीद बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियों की निगाह अमेरिका पर भी है। सूत्रों ने बताया कि आईओसी ने पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा से कच्चे तेल की खरीद के लिए हाजिर निविदा निकाली है।

अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा

भारत अपनी कच्चे तेल की 85 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरा करता है। फरवरी में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं जिससे महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। भारत की अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021 के दौरान ओपेक देशों से कच्चे तेल की खरीद घटकर 74.4 प्रतिशत रह गई है। एक साल पहले समान अवधि में यह 79.6 प्रतिशत थी।

धर्मेंद्र प्रधान ने की थी अपील

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओपेक और ओपेक से जुडे देशों से कीमतों पर अंकुश के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील करते रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब ने इसके बजाय भारत को सलाह दी है कि वह उस तेल का इस्तेमाल करे जो एक साल पहले उसने दाम काफी नीचे आने पर खरीदा था और उसका भंडारण किया था।

महामारी के चलते 2020-21 में घरेलू विमानन यात्रियों की संख्या 10 साल में सबसे कम रही: इक्रा

मुंबई। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के चलते बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत में घरेलू विमानन यात्रियों की संख्या घटकर 10 साल के निचले स्तर 5.34 करोड़ रह गई। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक इससे पहले वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान सभी घरेलू विमानन परिचालन के जरिए कुल यात्रियों की संख्या 5.38 करोड़ रही थी। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष में महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के समय लगभग दो महीने तक किसी भी नियमित यात्री विमान सेवा ने उड़ान नहीं भरी। आईसीआरए की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2021 में घरेलू यात्री यातायात 77-78 लाख के आसपास रहने का अनुमान है, जो इससे पहले फरवरी के मुकाबले एक प्रतिशत की मामूली गिरावट को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 (25 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक) के लिए घरेलू यात्री यातायात लगभग 5.34 करोड़ रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग 62 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट को दर्शाता है।

वित्त मंत्री का मुद्राकोष की कोटा समीक्षा में ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने के लिये संगठन में कोटे की 16वीं आम समीक्षा के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच अधिक तालमेल का आह्वान किया। आईएमएफ प्रस्ताव के अनुसार कोटे की सामान्य समीक्षा 15 दिसंबर, 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। कोटा हिस्सेदारी में किसी प्रकार के समायोजन से उभरते देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति के अनुरूप मतदान अधिकार में वृद्धि की उम्मीद है। इससे कुल मिलाकर गरीब सदस्य देशों के हितों और उनके प्रतिनिधित्व की रक्षा करते हुए वैश्विक संस्थान में उभरते बाजारों और विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीतियों के समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के जरिये कोविड-19 संकट से निपटने में पांच देशों के समूह की भूमिका पर महत्व दिया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का जोर समूह देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, उसमें निरंतरता लाने, संबंधों को मजबूत करने और आम सहमति बनाने पर है। भारत की अध्यक्षता में 2021 में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की यह पहली बैठक थी। बयान के अनुसार, "बैठक के दौरान ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने 2021 के लिए भारत द्वारा निर्धारित वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा की। इसके तहत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये उठाये गये कदम, नव विकास बैंक (एनडीबी) की गतिविधियां, सामाजिक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर सहयोग, आईएमएफ में सुधार, एसएमई के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन पर चर्चा की गयी।" वर्ष 2021 के लिये ब्रिक्स की प्राथमिकताओं और एजेंडे पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे परिणाम देने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए जो विशेष रूप से उभरते बाजारों में ब्रिक्स की जरूरतों और आकांक्षाओं तथा उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की उम्मीदों को प्रतिबिंबित करते हैं। बैठक के दौरान उन्होंने 2021 में नव विकास बैंक की प्राथमिकताओं और सदस्यता विस्तार के मुद्दों पर चर्चा की।

कोविड-19 महामारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। भारत ने 84 देशों को 6.45 करोड़ टीके की खुराक की आपूर्ति की है। सामाजिक बुनियादी ढांचे के महत्व और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर उन्होंने निजी क्षेत्र को जोड़ने और कर्ज के नये मॉडल तैयार करने में उनके महत्व पर भी जोर दिया।

सऊदी अरब से कच्चे तेल की खरीद घटाएगा भारत, दूसरे तेल उत्पादक देशों पर नजर

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिफाइनरी कंपनियां अगले महीने सऊदी अरब से कम कच्चे तेल की खरीद करेंगी। कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच ईंधन की मांग घटी है। कच्चे तेल की खरीद में विविधीकरण के लिए भारतीय कंपनियां पश्चिम एशिया के बाहर से आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और तीन अन्य रिफाइनरी कंपनियों ने मई में सऊदी अरब से 1.5 करोड़ बैरल के मासिक औसत की तुलना में सिर्फ 65 प्रतिशत की खरीद करने का फैसला किया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने यह जानकारी दी है। भारत ने सऊदी अरब से कीमतों पर अंकुश रखने के लिये कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। सऊदी अरब ने भारत के इस आग्रह को नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने पिछले महीने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से पश्चिम एशिया से बाहर से आपूर्ति पर ध्यान देने को कहा। सूत्रों ने बताया कि आईओसी और अन्य रिफाइनरी कंपनियां सऊदी अरब या ओपेक देशों से निश्चित मात्रा के अनुबंध के स्थान पर हाजिर या मौजूदा बाजार से अधिक कच्चा तेल खरीदने का प्रयास कर रही हैं। अपने इन प्रयासों के तहत कंपनियों ने गुयाना से लेकर नॉर्वे से नया कच्चा तेल खरीदा है। इसके अलावा खरीद बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियों की निगाह अमेरिका पर भी है। सूत्रों ने बताया कि आईओसी ने पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा से कच्चे तेल की खरीद के लिए हाजिर निविदा निकाली है। भारत की अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021 के दौरान ओपेक देशों से कच्चे तेल की खरीद घटकर 74.4 प्रतिशत रह गई है। एक साल पहले समान अवधि में यह 79.6 प्रतिशत थी। भारत अपनी कच्चे तेल की 85 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरा करता है। फरवरी में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं जिससे महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओपेक और ओपेक से जुडे देशों से कीमतों पर अंकुश के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील करते रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब ने इसके बजाय भारत को सलाह दी है कि वह उस तेल का इस्तेमाल करे जो एक साल पहले उसने दाम काफी नीचे आने पर खरीदा था और उसका भंडारण किया था।

क्या है जीएसटी में ई-इनवॉइस सिस्टम

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण

अन्य प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण भी ई-इनवॉइसिंग विशेषता रही है। आरबीआई द्वारा ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) की स्थापना सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई थी ताकि MSMEs को उनके इनवॉइस का 'ट्रेड' करने और प्रतिस्पर्धी दरों पर फाइनेंस तक पहुंच प्राप्त हो सके। अब, सप्लायर्स को TReDS पोर्टल्स पर ऐसे इनवॉइस विवरण दर्ज करने होंगे। एक बार जब ई-इनवॉइसिंग को मध्यम और छोटे व्यवसायों तक बढ़ाया जाएगा, रिपोर्ट किए गए ई-इनवॉइस का विवरण ऊ्रीअए डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उन पोर्टल्स पर इनवॉइस डेटा के री-एंट्री की आवश्यकता को कम किया जा सकता है।

आने वाले समय में होगा गेम चेंजर

ई-इनवॉइसिंग (e-invoicing) में जिस तरह से इसमें परिवर्तन हो रहे हैं और नवाचारों यानी इनोवेशन (Innovation) की गति बढ़ रही है, खासकर फिनटेक डोमेन में, ई-इनवॉइस आने वाले समय में और ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकता है। जिसे देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ई-इनवॉइसिंग बिजनेस इको-सिस्टम के लिए गेम चेंजर बनने जा रहा है।

अदाणी पोर्ट्स ने कृष्णापत्तनम पोर्ट में अपना स्वामित्व 100% किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी और डायवर्सिफ़ाइड अदाणी ग्रुप की प्रमुख परिवहन शाखा, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड एपीएसईज़ेड,ने अदाणी कृष्णापत्तनमपोर्ट लिमिटेड, कृष्णापत्तनम पोर्ट में 2,800 करोड़ रुपये में रेजिडुअल 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। इस अधिग्रहण से कृष्णापत्तनम पोर्ट में एपीएसईज़ेड की हिस्सेदारी 75% से बढ़कर 100% हो जाएगी। अक्टूबर 2020 में अधिग्राहित किए गए 75ऱ स्वामित्व के साथ, अधिग्रहण का अर्थ 10.3 गुने के मल्टिपल्स वाले ईवी/वित्त वर्ष 21 के ईबीआईटीडीए सहित13,675 करोड़ रुपये के एंटरप्राइज वैल्यू से है। कृष्णापत्तनम पोर्ट चेन्नई पोर्ट्स से । 180 किमी की दूरी पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के करीब आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कृष्णापत्तनम पोर्ट एक सभी मौसम में सक्रिय रहने वाला, गहरे पानी वाला बंदरगाह है, जिसकी 64 एमएमटीपीए की वर्तमान क्षमता वाली मल्टी-कार्गो सुविधा है। 20 किमी के वाटरफ्रंट और 6,800 एकड़ भूमि सहित, कृष्णापत्तनम पोर्ट में 300 एमएमटीपीए की मास्टर प्लान क्षमता है और 50 साल की रियायत प्राप्त है। इस पोर्ट से वित्त वर्ष 21 में 38 एमएमटी वॉल्यूम, 1,840 करोड़ रुपये का राजस्व और 1,325 करोड़ रुपये कर ईबीआईटीडीए हासिल होने की उम्मीद है। अधिग्रहण के बाद से, कृष्णापत्तनम पोर्ट ने व्यावसायिक प्रक्रिया की पुनर्रचना पर ध्यान केंद्रित किया है जिसके परिणामस्वरूप ईबीआईटीडीए मार्जिन वित्त वर्ष 2020 के 57% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 72% हो गया है। एपीएसईज़ेड के चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर एवं होलटाइम डायरेक्टर श्री करण अदाणी ने कहा कि 'कृष्णापत्तनम पोर्ट में हमारा स्वामित्व एपीएसईज़ेड के 2025 तक 500 एमएमटी के लक्ष्य के प्रति लिए और भारत के पश्चिम तथा पूर्वी तटों के बीच कार्गो के बीच बराबरी लाने की हमारी व्यापक रणनीति के लिए मजबूती प्रदान करता है। कृष्णापत्तनम पोर्ट 2025 तक दोगुना ट्रैफिक संभालने की राह पर है और यह एक मल्टी-प्रॉडक्ट और कार्गो एनहांसमेंट रणनीति के जरिये नियोजित पूंजी पर रिअर्न बढ़ाते हुए, उच्च विकास प्रदान करेगा। हमें विश्वास है कि हम 2025 तक कृष्णापत्तनम पोर्ट में थ्रूपुटको दोगुना और ट्रिपल ईबीआईटीडीए को तिगुना करने में सक्षम रहेंगे। हम कृष्णापत्तनम पोर्ट को दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए प्रवेश द्वार बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। पोर्ट के साथ उपलब्ध बड़ी औद्योगिक भूमि के साथ हम कृष्णापत्तनम को एक मैन्यूफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर बना देंगे।'

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के ग्राहकों के लिये लेकर आया हरित ऊर्जा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मुंबई का सबसे बड़ा बिजली वितरक अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) मुंबई द्वारा ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) को अपनाये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्राहकों के रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये एईएमएल मुंबई ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ग्राहकों के पास रिन्यूएबल एनर्जी के लिये अपने लक्ष्य निर्धारित करने की लोचशीलता होगी। एईएमएल स्थायित्व के लिये प्रतिबद्ध है और पेरिस समझौते के तहत अपारंपरिक योग्य ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार काम कर रहा हैं। एईएमएल साल 2023 तक ऊर्जा की अपनी जरूरत के 30 प्रतिशत से ज्यादा की सोर्सिंग अपारंपरिक ऊर्जा से करेगा और फिर इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाएगा, जिसके लिये आरटीसी पावर से अतिरिक्त 1000 मेगावाट लेने के लिये उसे एमईआरसी से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें 5 प्रतिशत से ज्यादा कम्पोनेंट आरई पावर का होगा।

एईएमएल के ग्राहक इन्हें अपना सकते हैं

1. अतिरिक्त 66 पैसे का भुगतान कर 700 प्रतिशत आरई पावर प्रदान करने की एमईआरसी दूवारा घोषित मौजूदा योजना के अंतगत आरई पावर खरीदने के विकल्प ले सकते है

2. एईएमएल अपने गाहकों को आरई प्रमाणपत्र पदान कर सकेगा, क्योंकि उसे वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्थान में हाइब्रिड सौर एवं पवन उत्पादन से 700 मेगावाट की आपूर्ति मिलेगी। इसमें ग्रीन एनर्जी के महत्वपूर्ण कम्पोनेंट के साथ अतिरिक्त 1000 मेगावाट बिजली भी जुड़ेगी (इसे एमईआरसी के पास अनुमोदन के लिये भेजा जा चुका है)।

एमईआरसी के अनुमोदन के अनुसार, एईएमल (महाराष्ट्र के अन्य सभी डिस्कॉम्स की तरह) अब अपने ग्राहकों को 66 पैसा प्रति यूनिट के अतिरिक्त टैरिफ के साथ नवीकरण योग्य ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा से जुड़ी उनकी 100 प्रतिशत जरुरत पूरी करने का विकल्प दे रहा है।

एईएमएल की नई पहल से उसके उन ग्राहकों को मदद मिलेगी, जिनका ग्लोबल फुटप्रिंट है और जिनका लक्ष्य अपारंपरिक स्त्रोतों से अपने कुल ऊर्जा उपभोग का 25 प्रतिशत या ज्यादा हिस्सा सोर्स करना है, और यह आरई प्रमाणपत्रों से हो सकता है। यह खोजपरक कदम ग्राहकों के स्थायित्व सम्बंधी लक्ष्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अपारंपरिक ऊर्जा की सीधी आपूर्ति और अप्रत्यक्ष समायोजन को मिलाकर एईएमएल अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों को मुंबई, भारत और वैश्विक स्तर पर स्थायित्व के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरने के योग्य बनाएगा। एईएमएल के सीईओ और एमडी श्री कंदर्प पटेल ने कहा, 'कंपनी अपनी अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार कर रही है, जिससे उसके ग्राहक अपनी ऊर्जा के स्रोत का चुनाव करने के लिये सशक्त होंगे और ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स सभी की पहुंच में होंगे और हरित ऊर्जा को अपनाना आसान होगा। हम मुंबई में बिना किसी बदलाव या रुकावट के हरित ऊर्जा की 100 प्रतिशत आपूर्ति और प्रमाणपत्रों की गारंटी दे सकते हैं। हम सभी ग्राहकों के लिये अपारंपरिक योग्य ऊर्जा के व्यक्तिपरक समाधान निर्मित करेंगे, ताकि वे अपारंपरिक ऊर्जा के अवसरों का पूरा फायदा लें और अपने सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को हासिल करें।'

मुंबई ग्रीन एनर्जी इनिशियेटिव एक स्वैच्छिक प्रोग्राम है, जो एईएमएल के मौजूदा और संभावित ग्राहकों के लिये है। सभी मौजूदा और नये ग्राहक इसमें भाग ले सकते हैं। एईएमएल ऐसे ग्राहकों के लिए मासिक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसमें बिजली की उनकी जरूरतों का वह प्रतिशत (ऱ) होगा, जिसे अपारंपरिक ऊर्जा से सोर्स किया गया हो।

आरबीआईः 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5 फीसदी रहने का अनुमान

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 10.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी ने आर्थिक वृद्धि दर में सुधार को लेकर अनिश्चितता पैदा की है। अपनी ताजा नीति समीक्षा में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के 10.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया है।

समीक्षा में कहा गया कि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए जीडीपी वृद्धि के 2021-22 में 10.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 26.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 8.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही मे 6.2 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि सभी की सहमति से यह भी निर्णय लिया कि टिकाऊ आधार पर वृद्धि को बनाए रखने के लिए जब तक जरूरी हो, उदार रुख को बरकरार रखा जाएगा और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को कम करने के प्रयास जारी रहेंगे।

आरबीआई ने प्रमुख उधारी दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए जरूरत पड़ने पर आगे कटौती की बात कहकर उदार रुख को बरकरार रखा। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा, ताकि उत्पादक क्षेत्रों को ऋण आसानी से मिले। आरबीआई ने कहा कि हालांकि विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की कंपनियां मांग में बढ़ोतरी को लेकर आशावादी हैं, लेकिन दूसरी ओर कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने से उपभोक्ता विश्वास कमजोर हुआ है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, अन्य ऊर्जा कंपनियों ने हाइड्रोजन गठजोड़ बनाया

मुंबई। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुवाई में कई वैश्विक ऊर्जा और औद्योगिक कंपनियां मंगलवार को ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव को लेकर नया संगठन बनाने के लिये एक मंच पर आयीं। यह संगठन इंडिया एच2 एलायंस (आईएच2ए) कहलाएगा। इसका मकसद देश में शुद्ध रूप से शून्य कार्बन ऊर्जा का रास्ता तैयार करने के लिये हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण में मदद करना है। मंच की तरफ से जारी बयान के अनुसार यह संगठन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण की दिशा में कार्य करेगा। साथ ही हाइड्रोजन के दोनों रूपों (नीला और हरित) के उत्पादन और भंडारण में मदद करेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले औद्योगिक संकुलों तथा हाइड्रोजन युक्त ईंधन बैटरी के जरिये परिवहन व्यवस्था के विकास में भी मदद करेगा। हालांकि, बयान में मंच के अन्य संस्थापक सदस्यों के नाम नहीं बताये गये हैं। यह संगठन औद्योगिक संकुलों, रिफाइनरीज, उर्वरक, सीमेंट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देगा।

आईएमएफ ने किया ये खुलासा

क्या अब लद रहे हैं डॉलर के एकछत्र राज करने के दिन?

पिछले साल विदेशी मुद्रा भंडारों में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये बात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ताजा आंकड़ों से सामने आई है। गौरतलब है कि डॉलर दुनिया भर में कारोबार की मुख्य मुद्रा है। इसलिए सरकारें अपने विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी अधिक से अधिक मात्रा रखने की कोशिश करती हैं।

साल 2020 में विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर का हिस्सा गिर कर 59 फीसदी रह गया। इसके पहले 1995 में ये हिस्सा 58 फीसदी रहा था। अब आई इस गिरावट का कुछ कारण तो मुद्राओं की कीमत में उतार-चढ़ाव है, लेकिन एक बड़ा कारण विदेशी व्यापार में दूसरी मुद्राओं खास कर चीन के युआन की बढ़ रही भूमिका भी है।

इसके बावजूद अभी भी दुनिया के अलग-अलग देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा सबसे बड़ा है। पिछले साल की चौथी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडारों में सात ट्रिलियन डॉलर जमा था। इसके पहले तीसरी तिमाही में ये रकम 6.939 ट्रिलियन डॉलर थी।

पिछले साल विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरोपियन यूनियन की मुद्रा-यूरो का हिस्सा सात फीसदी बढ़ा। ये रकम 2.52 ट्रिलियल डॉलर के बराबर तक पहुंच गई। पिछले साल की चौथी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडारों में जमा यूरो में 21.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 2014 के बाद की यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके पहले आर्थिक मंदी के समय 2009 में विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरो का हिस्सा बढ़ कर 28 फीसदी हो गया था। बहरहाल, सबसे ज्यादा ध्यान युआन की बढ़ी मात्रा ने खींचा है। पिछले साल सभी चार तिमाहियों में विदेशी मुद्रा भंडारों में युआन की मात्रा बढ़ती रही। साल भर में कुल मिला कर इसमें 2.25 फीसदी बढ़ोतरी हुई। अब दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में इसका हिस्सा नौ फीसदी हो गया है। गौरतलब है कि विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में युवान नया खिलाड़ी है। आईएमएफ ने इसका रिकॉर्ड रखने की शुरुआत 2017 में जाकर की थी। बीते तीन वर्षों में चीन सरकार ने विभिन्न देशों के साथ कारोबार आपसी मुद्रा में करने के समझौते किए हैं। चीन की योजना आखिरकार विदेश व्यापार में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की है। 2020 में इस बात के संकेत मिले कि चीन अपनी मंशा पूरी करने में भले ही धीमी रफ्तार से, लेकिन सफल हो रहा है। ताजा आंकड़ों को इसी सिलसिले में देखा जा रहा है।

कैनेडियन इम्पेरियल बैंक ऑफ कॉमर्स में स्ट्रेटेजिस्ट बिपन राय ने ब्लूमबर्ग टीवी से कहा- 'गति धीमी है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि उसका मतलब यह है कि दुनिया बहु-मुद्रा ढांचे की तरफ बढ़ रही है।' लेकिन अमेरिकी कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग फर्म बैनोकबर्न ग्लोबल में स्ट्रेटेजिस्ट मर्क चैंडलर ने वेबसाइट आरटी.कॉम से कहा कि विदशी मुद्रा भंडारों में अमेरिकी डॉलर के हिस्से में आई गिरावट एक अस्थायी घटना है। इसकी वजह चौथी तिमाही में अलग-अलग मुद्राओं की तुलना में डॉलर की कीमत में आई गिरावट है। उन्होंने कहा कि डॉलर का हिस्सा 59 फीसदी तक आ गिरना महज आंकड़ों का शोर है। इसकी एक वजह डॉलर की कीमत में गिरावट रही, तो दूसरी वजह दुनिया में यूरो की बढ़ी मांग है। लेकिन इस साल की पहली तिमाही में डॉलर की कीमत बढ़ी है, उससे सारी सूरत पलट जाएगी।

लेकिन शेयर बाजार के कुछ जानकारों की राय है कि डॉलर के हिस्से में आई गिरावट स्थायी है। इसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की कीमत में जारी उतार-चढ़ाव के कारण लोग अब सोना या चांदी में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। वेबसाइट आरटी.कॉम के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक ब्रोकर पीटर शिफ ने कुछ पहले एक पॉडकास्ट में कहा था कि डॉलर के एकछत्र राज करने के दिन अब लद रहे हैं।

डॉलर में तेजी व टीकाकरण से रिकॉर्ड स्तर से 11200 रुपये फिसला सोना

सोने में गिरावट जारी है और पिछले सात महीने में यह रिकॉर्ड स्तर से 20 प्रतिशत यानी 11,200 रुपये नीचे आ गया है। सोना 7 अगस्त, 2020 को 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 6 अप्रैल, 2021 को गिरकर 45,000 पर आ गया।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और डॉलर में पांच महीने की बड़ी मजबूती से कम हुआ सोने में आकर्षण

डॉलर में मजबूती व दुनियाभर में चल रहे टीकाकरण अभियान से भी सोने पर दबाव बढ़ा।आईआईएफएल सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि 2020 में डॉलर काफी नीचे आ गया था, जिससे सोने को समर्थन मिल रहा था। अब डॉलर मजबूत होकर 5 महीने के शीर्ष पर चल रहा है। इसके अलावा, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आकर्षण बढ़ा, जिससे सोना इस साल पहली तिमाही में 200 डॉलर लुढ़क गया। यह 40 साल में सोने की सबसे खराब शुरुआत है। अभी सोना 1,733 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा है। केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने कहा, महामारी से उबरने के लिए दुनियाभर के देशों ने राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ा व वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी, जिससे निवेशकों ने ज्यादा मुनाफे वाले संसाधनों की ओर रुख करते हुए इक्विटी, क्रूड ऑयल और बेस मेटल जैसे रिस्की एसेट में निवेश शुरू कर दिया। इससे भी सोने में गिरावट रही।

मांग में गिरावट का भी असर

भारत और चीन सोने के बड़े खरीदार हैं। लेकिन, भारत में दिवाली एवं चीन में न्यू ईयर पर भी सोने की मांग में गिरावट रही। इससे आयात प्रभावित हुआ। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2020 में सोने की मांग 35 प्रतिशत घट गई, जिससे आयात 47 प्रतिशत घटकर 344.2 टन पर आ गया।

40,000 तक पहुंच सकता है दाम

कासगंज यूपी के जिला सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने कहा, सोने का भाव एमसीएक्स पर निर्भर करता है। लॉकडाउन में अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद होने से अगस्त, 2020 में सोना 56,000 पार हो गया था। उड़ानें शुरू होने पर इसमें 11,000 रुपये गिरावट आई है। उड़ानें सामान्य होने पर सोना 40,000 रुपये तक आ सकता है।

दिवाली तक 52,000 पहुंचेगा

अजय केडिया के मुताबिक, विभिन्न वजहों से सोना दिवाली तक फिर 52,000 पर पहुंच सकता है अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल में ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इससे लंबी अवधि में सोने को समर्थन मिलेगा। मौजूदा तेजी को देखते हुए इक्विटी में निवेश बेहतर विकल्प नहीं है। रियल एस्टेट में जोखिम बना हुआ है। नवंबर-दिसंबर के बाद बिटक्वाइन में बड़ी गिरावट आई है। संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन की चिंताएं बढ़ रही हैं। इससे रिस्की एसेट में निवेश प्रभावित होगा। अमेरिकी सरकार ने बाजार में जो पूंजी डाली है, वह 100 साल में सबसे ज्यादा है। ऐसी लिक्विडिटी पंपिंग से महंगाई बढ़ती है, जिससे सोने को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

पीएफ से जुड़ी कोई है शिकायत तो ऐसे करायें दर्ज,

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रक्रिया को बनाया आसान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अगर आपका भविष्य निधि संगठन में खाता है और उससे जुड़ी कोई शिकायत है तो उसे ऑनलाइन दर्ज कराकर उसका निदान पा सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों की शिकायत के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी खाताधारक की अपने पीएफ खाते जैसे- पीएफ ट्रांसफर, ईपीएफ की निकासी, ईपीएफ खाता या केवाईसी आदि से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप ऑनलाइन दर्ज कराकर उसका निदान पा सकते हैं। आप ईपीएफओ के ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप ईपीएफओ के ट्विटर हैंडल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसका हैंडल हैं ocialepfo http://epfigms.giv.in पर जाएं.

अब एक वेबपेज खुलेगा. जिसमें आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए चयन करना पड़ेगा। स्टेटस का मतलब है कि पीएफ सदस्य, ईपीएस पेंशनर, नियोक्ता या अन्य. अगर आपके पास ळँ्झहेग्दह ईब्सहू ध्ि (इझ्ध्) नहीं है तो इसमें से अन्य का विकल्प चुनें।

पीएफ खाते से जुड़ी शिकायत के लिए पीएफ सदस्य का स्टेटस चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना यूएएन नंबर और सेक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा।

उसके बाद यूएएन से जुड़े सभी विवरण आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे।

इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। साथ ही यह पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ई मेल पर भी भेजा जाएगा।

ओटीपी भरने के बाद उसकी जांच की जाएगी और आपसे आपके निजी विवरण के बारे में जानकारी मांगी जाएगी।

निजी विवरण भरने के बाद अपने पीएफ नंबर पर आपको क्लिक करना होगा जिसको लेकर आपको शिकायत दर्ज करानी है।

इसके बाद स्क्रीन पर एक पॉप-अप विंडो खुलेगा. इसमें से आपको रेडियो बटन का चयन करना होगा, जिससे संबंधित शिकायत आपको दर्ज करानी है।

अब आपको शिकायत की श्रेणी का चयन करना होगा, और विवरण देना होगा. अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो उसे अपलोड करना होगा।

एक बार शिकायत दर्ज हो गई तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा. जिसको आपको संभालकर रखना होगा।

जिसके जरिए आप अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में समय-समय पर जानकारी कर सकते हैं. शिकायत दर्ज कराने के बाद आप उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

आपको http://epfigms.gov.in पर जाकर व्यू स्टेटस का विकल्प खोलना होगा। वहां पर आपको शिकायत नंबर, मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी और सेक्योरिटी कोड डालना पडेगा. जिसके बाद आप अपनी शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं।

इसके बाद शिकायत की सही स्थिति आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। यहां तक की इसके बारे में भी जानकी दी रहेगी की कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय आपकी शिकायत को हल करने के लिए काम कर रहा है। वहां के अधिकारी के बारे में भी आपको सही जानकारी दी रहेगी. साथ ही अधिकारी का मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी भी मिल जाएगी।

लोकल लॉकडाउन भी अर्थव्यवस्था को पहुंचाएंगे गहरी चोट, आरबीआई गवर्नर ने जताई आशंका

नई दिल्ली। एजेंसी

मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से विकास को बनाए रखने के लिए समायोजित रुख को बनाए रखने के साथ महंगाई दर को तय लक्ष्य पर बनाए रखने का टारगेट रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था को फोकस कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना और आर्थिक विकास को बनाए रखना है। एमपीसी ने कहा कि 2021 में बंपर खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जिसमें अनाज की कीमतों में नरमी देखने को मिलेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हाल ही में संक्रमणों में वृद्धि ने आउटलुक को अधिक अनिश्चितता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि लोकल लॉकडाउन डिमांड और सप्लाई में आए सुधार पर असर डाल सकता है और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में आने में और देरी हो सकती है। कमेटी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है लेकिन कहा कि टीकाकरण अभियान से ग्रोथ को तेजी मिलेगी। विशेषज्ञों ने उम्मीद की है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि, कोविड -19 मामलों की संख्या में वृद्धि और देश के कुछ हिस्सों में नए लोकल लॉकडाउन के बीच 'डोविश'रुख रह सकता है। ब्रिकवर्क्स रेटिंग ने कहा था कि कोरोनोवायरस के प्रसार में वृद्धि और देश के प्रमुख हिस्सों में वायरस को फैलाने के लिए लोकल लॉकाडाउन को देखते हुए दरों में बदलाव की उम्मीद कम थी। आईएमएफ ने मंगलवार को 2021 में भारत के लिए चीन की तुलना में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया। वाशिंगटन स्थित वैश्विक वित्तीय संस्थान ने विश्व बैंक के साथ वार्षिक स्प्रिंग मीटिंग से पहले अपनी वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक में कहा कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.9 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

RBI Monetary Policy

जानें आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक की 13 अहम बातें

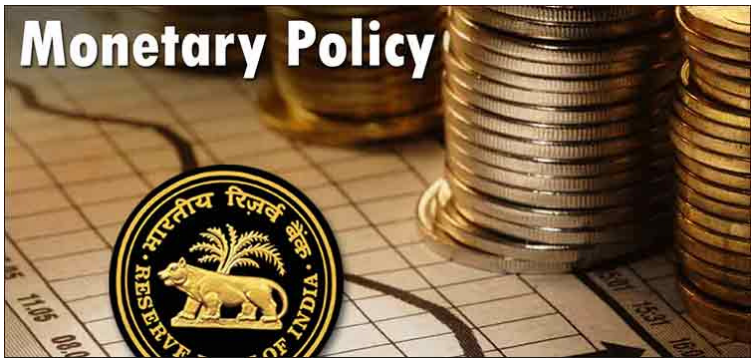

मुंबई। एजेंसी

कोविड-19 संक्रमण के ताजा मामलों और मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रमुख उधारी दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए जरूरत पड़ने पर आगे कटौती की बात कहकर उदार रुख को बरकरार रखा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो दर को चार प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा, ''सभी की सहमति से यह भी निर्णय लिया कि टिकाऊ आधार पर वृद्धि को बनाए रखने के लिए जब तक जरूरी हो, उदार रुख को बरकरार रखा जाएगा और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को कम करने के प्रयास जारी रहेंगे।''

आरबीआई गवर्नर ने आज क्या कुछ कहा है

■आरबीआई ने लगातार पांचवी बार नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा, रेपो रेट चार प्रतिशत पर। ■ चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 10.5 प्रतिशत पर बरकरार। ■ वृद्धि को समर्थन देने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति में उदार रुख को बनाए रखेगा। ■ मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर बनाए रखा जाएगा। ■ हाल में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी ने आर्थिक सुधार को लेकर अनिश्चितता पैदा की है, वायरस के संक्रमण पर काबू पाने की जरूरत। ■ जून और सितंबर तिमाही में क्रमशः 26.2 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान, जबकि दिसंबर और मार्च तिमाही में यह आंकड़ा क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत रह सकता है। ■खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को संशोधित कर 2020-21 की मार्च तिमाही के लिए पांच प्रतिशत किया गया। ■ जून और सितंबर तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रह सकती है। ■प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण मिले। ■नए ऋण के लिए नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सुविधा। ■ स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक अवरोधों से वित्तीय कंपनियों को बचाने के लिए जो भी करना होगा, वह किया जाएगा। ■भुगतान बैंकों के प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक के लिए अधिकतम शेष सीमा को दिन के अंत में एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया। ■परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के कामकाज की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया।

Share Market:

आरबीआई की घोषणाओं से झूमा बाजार, 49600 के पार बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की घोषणाओं का पॉजिटिव असर शेयर बाजार पर नजर आया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 460.37 अंक यानी 0.94 फीसदी चढ़कर 49661.76 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 135.55 अंक यानी 0.92 फीसदी की तेजी के साथ 14819.05 के स्तर पर बंद हुआ।

कल हरे निशान पर बंद हुआ बाजार

कल हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 42.07 अंक यानी 0.09 फीसदी की छलांग लगाकर 49,201.39 के पार बंद हुआ। वहीं, एनएसई का निफ्टी 45.70 अंक यानी 0.31 फीसदी चढ़कर 14,683.50 के लेवल पर बंद हुआ। कल सुबह एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बढ़त से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 से अधिक अंक चढ़ गया था लेकिन शाम तक शेयर बाजार में उतनी तेजी बरकरार नहीं रख पाया।

एस रमन्न सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र ने एस रमन्न को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सरकारी बयान के मुताबिक यह नियुक्ति तीन साल की होगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निदेशक स्तर की नियुक्तियों के बारे में सिफारिश करने वाले निकाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने दिसंबर में इस पद के लिए रमन्न के नाम की सिफरिश की थी। वह भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के 1991 के बैच के अधिकारी है। रमन्न इस समय नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लि' के मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं।

गिफ्ट कार्ड और गिफ्ट वाउचर पर कब लगेगा जीएसटी, दूर हुआ कनफ्यूजन

नई दिल्ली। एजेंसी

क्या गिफ्ट वाउचर पर लगने वाला टैक्स गिफ्ट कार्ड से अलग हो सकता है। गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट कार्ड पर जीएसटी के मुद्दे पर लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन Appellate Authority for Advance Ruling (AAAR) ने इस पर कनफ्यूजन दूर कर दिया है। AAAR ने 30 मार्च को अपने फैसले में कहा कि गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट कार्ड के सप्लाई का समय डेट ऑफ इश्यू होगी।

AAAR ने साफ किया है कि जीएसटी वाउचर की सप्लाई पर नहीं लगाया जाएगा लेकिन रिडेंपशन के समय गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि जीएसटी के भुगतान का समय जीएसटी कानून के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। दरअसल एक अलग फैसले से भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। इसमें कहा गया था कि वाउचर की सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। इसका रेट इस बात पर निर्भर करेगा कि वाउचर पेपर से बना है या मैग्नेटिक स्ट्रिप से।

ग्रे एरिया

ईवाई इंडिया में टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि वाउचर पर टैक्स हमेशा से ही ग्रे एरिया रहा है। जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद यह स्थिति बरकरार है। तमिलनाडु एएआर ने एक फैसले में कहा था कि वाउचर की सप्लाई पर 12 या 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। इससे भ्रम की स्थिति बनी थी। जीएसटी फ्रेमवर्क में गुड्स की सप्लाई का समय बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि जीएसटी खपत आधारित टैक्स है।

संसद GST को नागरिकों को लिए आसान बनाना चाहती थी, लेकिन लागू करने के दौरान यह मकसद से भटक गया: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी सिटिजन फ्रेंडली टैक्स हो, लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू किया जा रहा है, वह इसके मकसद को खत्म कर रहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कह सकता।

हिमाचल प्रदेश जीएसटी के एक प्रावधान को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी सिटिजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर बने। लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू कराया जा रहा है, इसका मकसद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई और कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कह सकता। हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि मामले की कार्यवाही पेंडिंग रहने के दौरान अधिकारी चाहे तो बैक अकाउंट समेत अन्य प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। जीएसटी एक्ट की धारा-83 में प्रावधान है कि अगर कोई मामला

पेंडिंग है और कमिश्नर ये समझता है कि सरकार के राजस्व के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है तो वह संबंधित पक्षकार (जिनके टैक्स का मामला है) की संपत्ति और बैंक अकाउंट आदि अटैच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई और कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कह सकता। संसद ने जीएसटी का जो स्ट्रक्चर बनाया वह सिटिजन फ्रेंडली बनाया गया था लेकिन जिस तरह से लागू कराया जा रहा है वह इसके मकसद से भटक चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट की धारा-83 को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सरकार ने अब तक 3.49 लाख टन गेहूं खरीदा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने 2021-22 के विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक 3.49 लाख टन गेहूं खरीदा है, जिसका मूल्य 691 करोड़ रुपये रहा है।

रबी विपणन सत्र (आरएमएस) के लिए अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हाल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेहूं की खरीद शुरू की गई है। बयान के मुताबिक पांच अप्रैल तक 3.49 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई, जिससे 4.45 लाख किसानों को 690.82 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य मिला है। बयान में आगे कहा गया कि चालू खरीफ विपणन सत्र (अक्टूबर-सितंबर) 2020-21 में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है।

बृहस्पति ने बदला अपना घर,जानें क्या होगा असर?

बृहस्पति ग्रह मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है। 12 साल बाद ये ग्रह कुंभ राशि में रहेगा। साल 2021 में गुरु का ये पहला राशि परिवर्तन है। अभी तक देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति अपनी नीच राशि में शनि के साथ थे और अब शनि की ही राशि कुंभ में आ गए हैं। इस राशि में ये 13 सितंबर तक रहेंगे। इसी बीच यह ग्रह 20 जून को वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा। फिर ऐसे ही चलते हुए 14 सितंबर को वापस मकर राशि में आ जाएगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को सीधी चाल से चलेगा और 20 नवंबर को फिर कुंभ राशि में आ जाएगा।

शनि की राशि में गुरु के आ जाने से अच्छे लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। देश के पूर्वी राज्यों में उपद्रव होने की आशंका है। शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितता रहेगी। प्रशासन और मंत्रियों के तालमेल में कमी आ सकती है। धार्मिक गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। राजनीति में उथल-पुथल बनी रहेगी।

गुरु राशि परिवर्तन अप्रैल 2021

मेष- व्यवसाय में किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ करेंगे। हेल्थ में सुधार आते रहेंगे। जॉब में सकारात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा में सफलता मिलेगी। नारंगी व पीला रंग शुभ है। प्रत्येक गुरुवार को अन्न का दान करें।

वृषभ- जॉब में आपकी स्थिति अब बहुत ही बेहतर होगी। आप व्यवसाय को और बेहतर करेंगे तथा कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। छात्रों के करियर को विस्तार मिलेगा। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल का दान करें। सफेद रंग शुभ है।

मिथुन- कुंभ में गुरु का गोचर बहुत ही शुभ है। जॉब व व्यवसाय में लाभ है। धन के लेन-देन के प्रति कोई भी लापरवाही न करें। प्रतिदिन अन्न का दान बहुत ही शुभ है। आसमानी व सफेद रंग शुभ है। गाय को प्रत्येक गुरुवार को भोजन कराएं।

कर्क- जॉब से संबद्ध जातकों के लिए सफलता का समय है। मकान या वाहन क्रय कर सकते हैं। जॉब में मित्र आपकी मदद करेंगे। सफेद व पीला रंग शुभ है। प्रतिदिन श्री विष्णुसहस्रनाम का पाठ करें। चने की दाल का दान करते रहें।

सिंह- गुरु का कुंभ गोचर शुभ है। जॉब में प्रोमोशन व व्यवसाय में सफलता का समय है। राजनीतिज्ञ सफल रहेंगे। रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। वाहन प्रयोग के प्रति सचेत रहें। नारंगी रंग शुभ है। प्रत्येक गुरुवार को गाय को भोजन देते रहें। भगवान विष्णु की उपासना करते रहें।

कन्या- गुरु का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही टर्निंग प्वॉइंट लेकर आया है। जॉब संबंधित कई महत्वपूर्ण व बड़े निर्णय इस समय लेंगे। पीला रंग शुभ है। प्रतिदिन श्री विष्णुसहस्रनाम का पाठ करें। छात्रों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर समय है। विष्णुजी की उपासना करते रहें।

तुला- यह समय जॉब के लिए बहुत ही शुभ है। यह गोचर छात्रों के लिए सफलता की प्राप्ति का है। गुरु व्यवसाय में आपकी रुकी योजनाओं को शुरू करेंगे। धार्मिक अनुष्ठान होंगे। नीला रंग शुभ है।

वृश्चिक- गुरु, गृह निर्माण संबंधी कई रुके कार्य पूर्ण करेंगे। व्यवसाय में रुके धन का आगमन होगा। जॉब में प्रगति के मार्ग बनेंगे। स्वास्थ्य सुख में भी प्रगति है। पीला रंग शुभ है।

धनु- छात्र सफल रहेंगे। व्यवसाय में प्रगति करेंगे। हर गुरुवार अन्नदान करते रहें। राजनीतिज्ञ अपने करियर में प्रगति को लेकर प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर खुश रहेंगे।

मकर- गुरु का कुंभ गोचर जॉब व व्यवसाय में बहुत कार्य करेगा। जॉब में विशेष सफलता मिलेगी। जॉब संबंधित किसी निर्णय को लेकर प्रसन्न रहेंगे। हरा व पीला रंग शुभ है। अन्न का दान करते रहें।

कुंभ- गुरु इस राशि में उपस्थित होकर आपको खुशहाली देंगे। छात्रों को करियर में आशातीत सफलता मिलेगी। गृह निर्माण संबंधी रुकी योजनाएं प्रारंभ होंगी। स्वास्थ्य सुख की बाधाएं दूर होंगी। पीला रंग शुभ है। प्रत्येक गुरुवार को गुरु के बीज मंत्र का जप करें व चने की दाल का दान करें।

मीन- व्यवसाय संबंधित कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा। शिक्षा में आपके लिए उपलब्धियों का समय है। गुरु का यह गोचर टेक्निकल व मैनेजमेंट फील्ड के छात्रों को कोई बड़ा अवसर दे सकता है। प्रत्येक गुरुवार को अन्न का दान करें। पीला व सफेद रंग शुभ है।

चैत्र नवरात्र शुरू होने से पहले घर लायें ये चमत्कारी चीज, अपकी हर समस्या होगी छू मंतर

चैत्र नवरात्र का आरंभ ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश दहशत में है. कोरोना बहुत तेजी से अपना फन फैला रहा है. इस बार नवरात्र का आरंभ दो विशेष शुभ योग के बीच होने जा रहा है. नवरात्र में अमृत योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इस शुभ संयोग में नवरात्रि पर मां भगवती की आराधना करने पर विशेष फल मिलता है. चैत्र नवरात्र धन और धर्म की बढ़ोतरी के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है. इस बार चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि, अश्वनी नक्षत्र, सर्वार्थ और अमृत सिद्धि योग से प्रारंभ होगी. वहीं, 22 अप्रैल दिन गुरुवार को मघा नक्षत्र और सिद्धि योग में दशमी तिथि के साथ संपन्न हो जाएगा. मां अपने भक्तों को दर्शन घोड़े पर सवार होकर देने आ रही हैं. वही मां की विदाई नर वाहन पर होगी. नवरात्रि में श्री यन्त्र स्थापित करने से मां की विशेष कृपा बरसाती हैं. श्री यन्त्र की सिद्धि भगवन शंकराचार्य ने की थी. दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ताकतवर यन्त्र इसे माना जाता है. वहीं, श्री यंत्र धन का भी प्रतीक हैं. यह यंत्र धन के अलावा शक्ति और अपूर्व सिद्धि का भी प्रतीक है. श्री यन्त्र के प्रयोग से सम्पन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है. इसके सही प्रयोग से हर तरह की दरिद्रता दूर की जा सकती है, इसके साथ ही अपकी हर समस्या छू मंतर हो जाएगी. श्री यन्त्र की आकृति दो प्रकार की होती है. उर्ध्वमुखी और अधोमुखी. भगवान शंकराचार्य ने उर्ध्वमुखी प्रतीक को सर्वाधिक मान्यता दी है. यन्त्र की स्थापना करने से पूर्व देख लें कि यह बिल्कुल ठीक बना हो. श्री यन्त्र आप काम करने के स्थान पर, पढ़ने के स्थान पर और पूजा के स्थान पर लगा सकते हैं. मान्यता है कि जहां पर श्री यन्त्र की स्थापना करें, वहां सात्विकता रखें और नियमित मंत्र जाप करें.

एकाग्रता के लिए श्री यन्त्र का कैसे प्रयोग करें

उर्ध्वमुखी श्री यन्त्र का चित्र अपने काम या पढ़ने की जगह पर लगाएं. वहीं, चित्र रंगीन हो तो ज्यादा बेहतर होगा. इसको इस तरह लगाएं कि यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो. जहां भी इसको स्थापित करें, वहां गंदगी न फैलाएं, नशा न करें.

विक्रम संवत से पहले भारत में कौनसा संवत था प्रचलित?

58 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने खगोलविदों की मदद से पूर्व प्रचलित कैलेंडर और हिन्दू पंचांग पर आधारित एक कैलेंडर को इजाद करवाया जिसे बाद में विक्रमादित्य संवत कहा जाने लगा। यही हिन्दुओं का सबसे शुद्ध कैलेंडर माना जाता है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर के पांच प्रकार हैं सौर, चंद्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास। विक्रम संवत में सभी का समावेश है। विक्रम संवत से पूर्व भारत में कौनसा संवत प्रचलित था जानिए। प्राचीन संवत : विक्रम संवत से पूर्व भारत में 6676 ईस्वी पूर्व से शुरू हुए प्राचीन सप्तर्षि संवत को हिंदुओं का सबसे प्राचीन संवत माना जाता है, जिसकी विधिवत शुरुआत 3076 ईस्वी पूर्व हुई मानी जाती है। सप्तर्षि के बाद नंबर आता है कृष्ण के जन्म की तिथि से कृष्ण कैलेंडर का फिर कलियुग संवत का। कलियुग के प्रारंभ के साथ कलियुग संवत की 3102 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई थी।

प्राचीन काल में दुनिया भर में चैत्र माह और मार्च को ही वर्ष का पहला महीना माना जाता रहा था। आज भी बहीखाते का नवीनीकरण और मंगल कार्य की शुरुआत मार्च में ही होती है। विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल की पहली तिथि से न केवल नवरात्रि में दुर्गा व्रत-पूजन का आरंभ होता है, बल्कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। मार्च से ही सूर्य मास अनुसार मेष राशि की शुरुआत भी मानी गई है। भारत में जब विक्रम संवत् के आधार पर नववर्ष प्रारंभ होता है, तो उसे हर राज्य में एक अलग नाम से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र में उगादिनाम, जम्मू-कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैशाखी, सिन्ध में चैटीचंड, केरल में विशु, असम में रोंगली बिहू आदि, जबकि ईरान में नौरोज के समय नववर्ष इसी दिन प्रारंभ होता है। हर राज्य में इसका नाम भले ही अलग हो लेकिन सभी यह जानते हैं कि इसका नाम नवसंवत्सर ही है।

गुड़ी पड़वा कब है, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

हिंदू नवसंवत्सर के दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। यह चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को आता है। इसे वर्ष प्रतिपदा या उगादि भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का इस दिन से ही नववर्ष शुरू होता है। गुड़ी के अर्थ की बात करें तो यह विजय पताका होता है। शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना तैयार की थी और उससे प्रभावी शत्रुओं का पराभव किया था। इसे विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जहां आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस दिन को उगादि तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व।

गुड़ी पड़वा तिथि और मुहूर्तः

गुड़ी पड़वा मंगलवार, अप्रैल 13, 2021

गुड़ी पड़वा तिथि- 13 अप्रैल 2021

प्रतिपदा तिथि प्रारंभ- 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार की सुबह 08 बजे से।

प्रतिपदा तिथि समाप्त- 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार की सुबह 10 बजकर 16 मिनट तक।

गुड़ी पड़वा महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ऐसे में इस दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। साथ ही कहा जाता है कि गुड़ी पड़वा के दिन सारी बुराईयों का नाश हो जाता है। वहीं, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है।

जानें कैसे मनाया जाता है गुड़ी पड़वा

महाराष्ट्र में इस दिन कई तरह के जुलूस आयोजित किए जाते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। साथ ही मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ त्यौहार का आनंद लेते हैं। कई लोग अपने घरों में अलग-अलग तरह के पारंपरिक व्यंजन जैसे पूरन पोली और श्रीखंड आदि बनाते हैं। महाराष्ट्र में मीठे चावल बनाए जाते हैं। इन्हें सक्कर भात कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय से शुरू होकर पूरे दिन अनुष्ठान चलते हैं।

गुड़ी पड़वा पूजा विधि

1. गुड़ी पड़वा के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि किया जाता है।
2. इसके बाद मुख्यद्वार को आम के पत्तों से सजाया जाता है।
3. घर के एक हिस्से में गुड़ी लगाई जाती है। इसे आम के पत्तों, पुष्प और कपड़े आदि से सजाया जाता है।
4. इसके बाद भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है और गुड़ी फहराते हैं।
5. गुड़ी फहराने के बाद भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है।

भारत की 5 टॉप माइलेज देनी वाली पेट्रोल कारें, टोयोटा और मारुती जैसी कंपनी भी हैं शामिल

नई दिल्ली। एजेंसी

आम तौर पर धारणा है कि डीजल कार, पेट्रोल कार के मुकाबले ज्यादा माइलेज देती है, जो कि पूर्णतया सच नहीं है। अब जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद लोग कार की माइलेज को लेकर काफी सोचने लगे है। ऐसे में हम आपको बताते हैं भारत में बिकने वाली 5 टॉप कार,जो आपको बहुत अच्छा माइलेज देंगी और इनकी शुरुआती कीमत भी बस 2।99 लाख रुपए है।

Maruti baleno- मारुती बलेनो भारत में बिकने वाली एक प्रीमियम हैचबैक कार है,जो अपने अच्छे माइलेज के लिए जानी जाती है। कंपनी ने इसमें 1.2 लीटर की क्षमता का न्ऊ पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि 82 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।मारुती की ये कार मैन्युअल और आटोमेटिक वैरिएंट्स के साथ आती है, हालाँकि इसका मैन्युअल वेरिएंट सबसे ज्यादा माइलेज देता है। कंपनी ने इसमें स्मार्ट हाइब्रिड (SHVS) तकनीक का इस्तेमाल किया है जो इस कार को बेहतर माइलेज देने में मदद करता है। इस कार की कीमत 5।90 लाख से 8।07 लाख रुपए तक है। ये कार आपको 23.87 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देगी।

Maruti Swift- ये कार कंपनी की एक बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार है जिसके नए मॉडल को कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। कंपनी ने इस कार में 1।2 लीटर क्षमता वाले नए डुअल जेट पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है जो 88 ंप्ज की पावर और 113 ऋ का टॉर्क जेनरेट करता है। ये कार 4 वैरिएंट्स के साथ आती है। इस कार की कीमत 5.73 लाख से लेकर 7।91 लाख रुपये तक है।ये कार आपको 23.20 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देगी।

Maruti Alto- मारुती आल्टो पुराने समय से ही देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जो अपने बेहतर माइलेज के लिए जानी जाती है। इस कार में कंपनी ने 796cc की क्षमता का पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है जो कि 47 bhp की पावर और 69 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।इस कार के कीमत 2।99 लाख से 4।48 लाख रुपये तक है।ये कार आपको 22.05 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देगी।

Maruti Dzire- मारुती की dzire इस सेगमेंट में सबसे बेहतर माइलेज देनी वाली कारों में से एक है।कंपनी ने इसमें ख सीरीज 1।2 लीटर की क्षमता का 4 सिलिंडर युक्त पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि 82 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स भी दिया गया है।इसकी कार की कीमत 5।94 लाख से 8।40 लाख रुपये तक है। ये कार आपको 23.26 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देगी।

Toyota Glanza- मारुति सुजुकी की बलेनो पर बेस्ड ये कार टोयोटा की एक प्रीमियम हैचबैक कार है।टोयोटा और सुजुकी के एक एग्रीमेंट के तहत इस कार को तैयार किया गया है।कंपनी ने इस कार में 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है।ये कार सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है।इस कार की कीमत 7.18 लाख से 7.90 लाख रुपये तक है जो आपको 23.87 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देगी।

श्रीलंका ने पामतेल आयात पर रोक लगाई, बागान मालिकों से इसके पौधे उखाड़ने को कहा

कोलंबो। एजेंसी

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में पामतेल के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। उन्होंने स्थानीय बागान कंपनियों को उनके लगाये गये पॉम पौधों में से 10 प्रतिशत को उखाड़ फेंकने और उसके स्थान पर रबड़ के पेड़ या अन्य पर्यावरण अनुकूल फसल लगाने को कहा है। श्रीलंका सरकार की इस पहल से घरेलू नारियल तेल उद्योग को लाभ मिल सकता है। राष्ट्रपति सचिवालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, पामतेल (कटुपोल) की खेती पर पूरी तरह से रोक होगी।

इसमें कहा गया है कि सीमा शुल्क महानिदेशक को भी इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया है और उन्हें सलाह दी गई है कि वे सीमा शुल्क विभाग में पाम तेल कार्गो को स्वीकृति देने से बचें। आयात एवं निर्यात नियंत्रण विभाग के महानियंत्रक को सलाह दी गई है कि इस आदेश को प्रभावी करने के लिए संबंधित राजपत्र आदेश जारी करे। राष्ट्रपति ने लगभग छह महीने पहले देश में पाम तेल की खेती पर धीरे-धीरे रोक लगाने का निर्देश दिया था। राष्ट्रपति सचिवालय ने इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया था कि ऐसी खेती करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से एक समय में 10 प्रतिशत पेड़ों को उखाड़ कर उसकी जगह हर साल रबर या पर्यावरण अनुकूल फसलों को लगाना होगा ताकि 'श्रीलंका को पाम खेती और पाम तेल के उपभोग'' से मुक्त किया जा सके।

आदेश में कहा गया है कि जब यह पूरी तरह से लागू हो जाता है, तो सरकार का इरादा पामतेल की खेती और पाम तेल की खपत को पूरी तरह से रोक देने का है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, श्रीलंका अपने देश में मलेशिया और इंडोनेशिया से सालाना लगभग दो लाख टन पाम तेल का आयात करता है। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया में उपभोक्ता संरक्षण सोसायटी ने फैसले का स्वागत किया है। सोसायटी के रंजीत विथानागे ने कहा कि इस निर्णय से स्थानीय नारियल तेल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

FoRes Billionaires List 2021:

दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की लिस्ट में जेफ बेजोस और एलन मस्क का जलवा

मुकेश अंबानी भी टॉप 10 में बरकरार

नई दिल्ली। एजेंसी

फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट की एनाउंसमेंट कर दी है। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट पहले स्थान पर बरकरार हैं। जेफ बेजोस के बाद इस लिस्ट में दूसरा नंबर है इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क का। टॉप टेन की लिस्ट में पहली बार डेटिंग एप के बंबल के चीफ व्हिटनी वोल्फ हर्ड जगह बनाने में असफल रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 177 अरब डॉलर हो गई है। वहीं एलन मस्क की कुल संपत्ति 151 अरब डॉलर है। वहीं टॉप टेन लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। फोर्ब्स के चीफ कंटेंट ऑफिसर लेन समाचार एजेंसी रायटर्स से कहा, 'अमीर और अमीर, बहुत अमीर हो गए हैं।' फोर्ब्स के अनुसार 2,755 नए अरबपति इस लिस्ट में शामिल हुए हैं।

ये हैं दुनिया के टॉप टेन रईस व्यक्ति

नाम	कुल संपत्ति (अरब डॉलर में)
जेफ बोजोस	177
एलन मस्क	151
बर्नार्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली	150
बिल गेट्स	124
मार्क जुकरबर्ग	97
वॉरेन बफेट	96
लैरी एलिशन	93
लैरी पेज	91.5
सर्गीब्रिन	89
मुकेश अंबानी	84.5

जेके टायर ने जेबीएम ऑटो लिमिटेड के साथ साझेदारी की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में भारतीय टायर उद्योग के प्रमुख और मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जेबीएम ऑटो लिमिटेड के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। जेबीएम ऑटो लिमिटेड सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों सहित भारत में सार्वजनिक गतिशीलता के उत्कृष्टा, सुविधाजनक और संवहनीय समाधानों की अग्रणी निर्माता हैं। इस साझेदारी के माध्यम से जेके टायर सिटी बस एप्लिकेशन में जेबीएम ऑटो के सिटीलाइफ सीएनजी और इकोलाइफ इलेक्ट्रिक बसों के लिए अपने स्मार्ट टायर डिवाइस के साथ फिट किए गए श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रेडियल टायर की आपूर्ति करेगा। जेके टायर और जेबीएम ऑटो ने स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों को विकसित करने के उद्देश्य से गठबंधन किया है जिसमें नवीनतम तकनीक शामिल है जो इष्टतम टिकाउपन और प्रदर्शन प्रदान करती है। इस सहयोग में दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में स्थापित 11 कार्यशालाओं में 24X7 सहायता के लिए जेके टायर पेशेवरों की एक समर्पित टीम के साथ 'टोटल टायर मैनेजमेंट' का एंड-टू-एंड स्वामित्व शामिल है। जेके टायर अपनी तरह का पहला क्लाउड बेस्डड मॉनीटरिंग सिस्टमम 'कनेक्टेड मोबिलिटी सॉल्यूशंस' स्थापित बेजोड़ परफॉर्मेंस प्रदान करेगा। जेके टायर महत्व पूर्ण तकनीकों और उत्पादों की पेशकश के माध्यम से टायर उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहा है जो ऑटोमोबाइल उद्योग में विविध व्यावसायिक वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टबर – सेल्सद एवं मार्केटिंग, श्री श्रीनिवासु अल्लाफन ने इस साझेदारी पर अपनी बात रखते हुए कहा, 'वाणिज्यिक क्षेत्र में बाजार अग्रणी होने के नाते, जेके टायर विभिन्नय वर्गों में भविष्य। के मोबिलिटी ट्रेंड्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार की दिशा में अपनीअटूट प्रतिबद्धता के लिए खड़ा है। हम विभिन्न निर्माताओं के साथ उन्नदत मोबिलिटी समाधानों को प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जेबीएम ऑटो लिमिटेड के साथ हमारी साझेदारी इसी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। '

गैर-तकनीकी विषयों में पढ़े युवा भी ले सकेंगे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना का लाभः प्रस्ताव

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनटीएस) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसके बाद डिग्री प्रशिक्षुता योजना में गैर तकनीकी विषयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को भी शामिल किया जा सकेगा। कौशल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, '' उच्चतर शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। '' उन्होंने बताया कि संशोधित योजना के तहत स्नातक, तकनीशियन और डिग्री प्रशिक्षुओं के शिक्षा प्रशिक्षण को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है ।

इसके तहत डिग्री प्रशिक्षुता में गैर तकनीकी विषयों (बीए/ बी कॉम/ बीएससी) आदि में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भी एनटीएस योजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है ।

स्नातकों, तकनीशियनों और डिग्री प्रशिक्षुओं के लिये वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान मानदेय राशि (स्टाइपेंड) की प्रतिपूर्ति के लिये अनुमानित लागत 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि युवाओं के लिये प्रशिक्षुता के अवसरों में और वृद्धि करने की दृष्टि से प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है । संशोधन के मसौदे पर संबंधि पक्षों के साथ विचार विमर्श चल रहा है।

नए वेरिएंट्स को पहचान नहीं पा रहा भारत, कोरोना से लड़ाई में लग सकता है झटका

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। हर दिन आने वाले नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में कोरोना के ताबड़तोड़ नए मामलों के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके अलग-अलग वेरिएंट को पहचान न पाना हो सकता है। भारत में इन वेरिएंट्स को पता लगाने में देरी हो रही है जिसकी वजह से तबाही कई गुणा ज्यादा हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इससे न सिर्फ इलाज बल्कि वैक्सीन का असर भी प्रभावित हो सकता है। सरकारी डेटा के मुताबिक, भारत अपने पॉजिटिव सैंपलों में से सिर्फ एक प्रतिशत को ही जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजता है। वहीं, ब्रिटेन कुल संक्रमितों के 8 प्रतिशत सैंपलों की जीनोम सिक्वेंसिंग करता है। बीते हफ्ते तो यूके में 33 फीसदी सैंपलों को सिक्वेंस किया गया। अमेरिका में भी एक हफ्ते में आए 4 लाख नए मामलों के 4 फीसदी सैंपलों की जांच की गई। बुधवार को भारत में कोरोना वायरस के 1 लाख 15 हजार नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 1.28 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अब भारत कुल संक्रमितों के मामले में सिर्फ ब्राजील और अमेरिका से पीछे है। भारत में महाराष्ट्र कोरोना का गढ़ बना हुआ है, जहां लगातार रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते साल दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय सफर कर आने वाले कुछ यात्रियों में कोरोना का यूके वाला वेरिएंट मिला था, जिसके बाद भारत ने राज्यों द्वारा संचालित 10 लैबोरेटरी को मिलाकर एक कंजोर्शियम बनाया था ताकि पॉजिटिव सैंपलों की सिक्वेंसिंग की जा सके। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 मार्च को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जनवरी से मार्च के बीच देश में सिर्फ 11 हजार 64 सैंपलों की ही सिक्वेंसिंग की गई, जोकि 0.6 प्रतिशत से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में 30 मार्च तक कोरोना के यूके वेरिएंट वाले 807 केस, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट वाले 47 केस और ब्राजील के वेरिएंट वाला एक केस मिल चुका था। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को 11 राज्यों के साथ मीटिंग के दौरान यह बताया था कि पंजाब में 80 फीसदी नए मामले कोविड-19 के यूके वेरिएंट की वजह से हैं। उन्होंने बताया था कि जीनोम सिक्वेंसिंग से ही इसकी पुष्टि हुई है। उन्होंने यह भी कहा था कि शादियों, स्थानीय निकाय चुनावों और किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

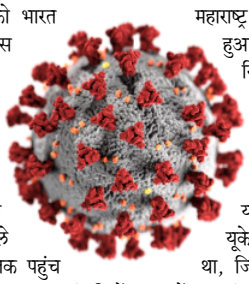

कोरोना : सितंबर में घटे तो - अचानक अप्रैल में क्यों बढ़ रहे हैं भारत में मामले, ये हैं पांच कारण

एजेंसी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सोमवार को देश में कोरोना के एक लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को इन दैनिक मामलों में हल्की राहत दिखी। वहीं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया था और महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम रवाना करने का फैसला लिया गया था। पिछले साल सितंबर के बाद से देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे। वहीं राष्ट्र में कोरोना का टीकाकरण अभियान भी जारी है लेकिन इसके बाद संक्रमित मामलों मे गिरावट नहीं दिख रही है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

पहली वजहः कोरोना से बचे लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है

डॉक्टर शाहिद जमील देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी तभी देखने को मिलेगी, जब एक बड़ी आबादी को कोविड-19 नहीं हुआ हो। देश में अब तक हुए सीरो सर्वे में हमने देखा कि एक बड़ी आबादी अब भी कोविड19 महामारी से बची थी, जो इंफेक्शन की चपेट में नहीं आए थे।

सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड डॉक्टर जुगल किशोर सीरो सर्वे के जरिए इस बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिन जगहों पर सीरो सर्वे हुए, हर इलाके में आंकड़े अलग आए थे, इसका मतलब साफ है कि कहीं 50 फीसदी लोगों को कोविड हुआ था, तो कहीं 20 फीसदी को, तो कहीं 30 फीसदी को। गांवों में ये थोड़ा और कम था। लोगों को बचाने के लिए सरकार ने उन्हें घर में रखा, बाहर निकलने पर पाबंदियां लगाई। लेकिन अब तक बचने का मतलब ये नहीं कि आगे कोविड-19 नहीं होगा।

RTGS और NEFT के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर

RBI ने डिजिटल पेमेंट की लिमिट की दोगुनी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (RTGS) सुविधा को नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अभी तक केवल बैंकों को ही यह सुविधा थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट की लिमिट को भी एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई एनाउंसमेंट के अनुसार अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क, ह्वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर और ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम प्लेटफार्म भी अब आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग कर सकेंगे। प्रेस को सम्बोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा, 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित केन्द्रीय भुगतान प्रणाली आरटीजीएस और एनईएफटी की सदस्यता कुछ अपवादों को छोड़कर सिर्फ बैंक तक ही सीमित था। जिसका दायरा अब बढ़ाया जा रहा है' इससे सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम, फोन पे, गूगल पेमेंट जैसे ऑनलाइन यूजर्स को होगा।

डिजिटल पेमेंट की लिमिट दो लाख तक बढ़ाई गई

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है। अब फोन पे, पेटीएम जैसे ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए कस्टमर दो लाख रुपये तक ट्रांसफर कर पाएंगे। पहले यह लिमिट एक लाख रुपये तक ही थी। हालांकि इस लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

क्या है आरटीजीएस और एनईएफटी

आरटीजीएस फंड ट्रांसफर करने की एक तेज प्रक्रिया है। इस सिस्टम के जरिए आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस का फुल फार्म Real Time Gross Settlement है। आरटीजीएस और NEFT में अगर अंतर देखा जाए तो दोनों का काम बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर है। एनईएफटी में जहां पैसे ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं है तो वहीं आरटीजीएस में आपको कम से कम दो लाख रुपये का ट्रांसफर करना होगा। एनईएफटी में फंड दूसरे खाते में पहुंचने में थोड़ा समय लगता है पर RTGS में यह तुरंत पहुंच जाता है। आईएमपीएस में तुरंत दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सर्विस सातों दिन 24 घंटे काम करती है।

सोलर पैनल, एसी व एलईडी लाइट्स के उत्पादन में PLI स्कीम को मिली मंजूरी

नई दिल्ली।एजेंसी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए दो क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी है। इनमें पहला है सोलर पैनल और दूसरा है व्हाइट गुड्स (एसी व एलईडी लाइट्स)। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने एक एमओयू को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने एसी और एलईडी उपकरणों के उत्पादन के लिए 6238 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। यह राशि 5 वर्षों में वितरित की जाएगी। गोयल ने बताया कि इसमें 5-6 फीसद इंसेंटिव मिलेगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर उपकरण एमएसएमई (MSME) बनाते हैं। ऐसे में एमएसएमई को फायदा होगा और बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से भारत को एसी और एलईडी उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। यह पीएलआई स्कीम भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी आगे लेकर जाएगी। दूसरी पीएलआई योजना हाई एफिशियेंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए है। गोयल ने बताया कि हाई एफिशियेंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स द्वारा लगभग 10 हजार मेगावाट की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का भारत में निर्माण होगा। जिसमें साढे चार हजार करोड़ रुपये का इज्ज दिया जायेगा। गोयल ने कहा कि इससे विदेशी कंपनियां भी भारत में आने के लिए प्रोत्साहित होंगी और भारत सोलर उपकरण के निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही बिजली की कीमतें कम होंगी। गोयल ने बताया कि इस योजना से 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व 1.10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। गोयल ने कहा, 'एलईडी लाइटिंग में आज भारत विश्व का लीडर है। उजाला योजना से एलईडी की कीमत 85 फीसद घट गयी। देश में अब लगभग सभी जगह एलईडी लगायी जा रही है, जिससे बिजली के बिल कम हुए और इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। गोयल ने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत के लिये पीएलआई योजना एक केंद्रीय बिंदु है। भारत ने 13 सेक्टर चुनें, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना योगदान दे सकें। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद पहली बार लाया गया है। इससे कम से कम 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने के अवसर मिलेंगे। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बड़ा उछाल मिलेगा। भारत ने पिछले 5 वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर या 1.5 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किया है। 13 सेक्टर में पीएलआई स्कीम 35 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी।

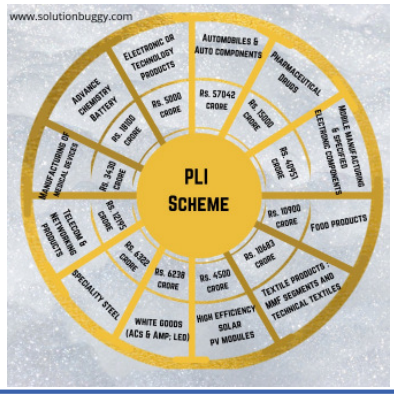

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।